नईदुनिया

संतों की वाणी जीवन को सही दिशा देती है : डॉ. यादव

- गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लिया
- गीता भवन, पुस्तकालय और संस्कृत विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संतों की वाणी मानव जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करती है और संस्कारों से ही समाज का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पर्व और उत्सव मानव कल्याण का संदेश देते हैं तथा समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पन्ना प्रवास के दौरान श्री किशोर मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने श्रीधाम वृंदावन से पधारे महंत स्वामी किशोरदास का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री ने गौसेवा, सभी धर्मों के पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाने तथा भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन और पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे तथा वृंदावन ग्राम की अवधारणा पर भी कार्य किया जा रहा है।

साथ ही पन्ना में प्रतिवर्ष तीन दिवसीय कथा उत्सव आयोजित करने तथा संस्कृत विद्यालय खोलने की घोषणा की।

केन्द्र सरकार युवाओं की भविष्य सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बताया कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोनम वांगचुक से भेंट कर विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की पहल, दृष्टिकोण और आगामी योजनाओं की रूपरेखा साझा की। सकारात्मक एवं सार्थक संवाद के उपरांत श्री वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पेपर लीक जैसे विषयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को अधिक सुदृढ़ करने एवं प्रत्येक विद्यार्थी के हितों की रक्षा के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

तकनीक और प्रशिक्षित पुलिस बल के दम पर सुरक्षित होगा सिंहस्थ-2028 : डीजीपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को गति देने के लिए शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी)' सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेशभर से मास्टर ट्रेनर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सेमिनार में प्रशिक्षण व्यवस्था की समीक्षा, फील्ड अनुभवों का आदान-प्रदान तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कहा कि सिंहस्थ-2028 विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और इसकी सफलता के लिए आधुनिक तकनीक, प्रभावी समन्वय तथा प्रशिक्षित पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस पिछले तीन वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से तैयारियों में जुटी है। प्रयागराज महाकुंभ-2025 से मिले अनुभवों को भी प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है।

डीजीपी ने बताया कि दो चरणों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशभर में 303 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं, जो अपने-अपने जिलों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमिका आधारित प्रशिक्षण दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय का ई-एचआरएमएस पोर्टल अंतिम चरण में है, जिससे सिंहस्थ के दौरान पुलिस बल की तैनाती और मानव संसाधन प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होगा।

सेमिनार में विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण को अधिक व्यवहारिक, तकनीक आधारित और सेवा भाव से जोड़ने पर बल दिया।

ओरछा धरोहर संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राज्य शासन ने ओरछा धरोहर दृष्टि योजना के अनुरूप परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति धरोहर एकीकृत प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन तथा वर्तमान और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा करेगी।

- विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की तैयारियों के बीच गठित की समिति

ओरछा को वर्ष 2027-28 के विश्व धरोहर चक्र में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए नामांकन प्रलेख तैयार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से धरोहर प्रबंधन व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

समिति में अपर मुख्य सचिव संस्कृति, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव वन और लोक निर्माण, पुरातत्व आयुक्त, निवाड़ी कलेक्टर तथा अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि पर्यटन सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें धरोहर प्रबंधन योजना के अनुरूप लागू कराने, विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धरोहर संरक्षण संबंधी अनुशंसाओं के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करेगी।

दतिया उपचुनाव में सिंधिया ने आशुतोष के लिए मांगे वोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में बड़ौनी, जिगना, निचरोली, चकरासागर और गोविंद नगर सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास और प्रगति को नई गति मिली है तथा जनता तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन विकास कार्यों की अपेक्षा परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता के अधिकारों की उपेक्षा की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने संगठन के समर्पित कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है और मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह, विधायक प्रीतम लोधी उपस्थित रहे।

फिर गरमाया भोजशाला विवाद, चालीस पीर दरगाह पर नहीं हुई जुमे की नमाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। यहां शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए भोजशाला के पास वाली जगह देने की मांग पर उड़ा हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने बीती 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज के लिए भोजशाला के पास जगह उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। न्यायालय ने कहा था कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने मालीवाड़ा

- मुस्लिम पक्ष भोजशाला के पास वाली जगह के लिए अड़ा, शहर में 350 सुरक्षाकर्मी तैनात

गांव में चालीसपीर दरगाह के पास नमाज की जगह निर्धारित की थी लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर गुरुवार देर रात जिला प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक चली बैठक में अन्य संभावित स्थानों का प्रस्ताव रखा गया लेकिन नमाज के वैकल्पिक स्थान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शुक्रवार को प्रशासन द्वारा निर्धारित मालीवाड़ा में चालीसपीर दरगाह के पास जुमे की नमाज अदा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की ओर से मौके पर सभी इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम समाज का कहना है कि उन्हें उनके पारंपरिक स्थान पर ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। धार के सदर अब्दुल समद ने कहा कि प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए इतनी दूर वैकल्पिक व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि चालीसपीर दरगाह के पास निर्धारित स्थान पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके बजाय जुमे की नमाज आसपास की मस्जिदों में अदा की जाएगी। इधर, जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार सुबह से ही शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। जावरा और इंदौर से पुलिस की दो विशेष कंपनियां बुलाई गई। पूरे नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

पदोन्नति प्रक्रिया में उलझन, हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें अटकीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में वर्ष 2025 के पदोन्नति नियम लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नई उलझन में फंस गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की प्रक्रिया में हुई चूक के कारण वर्ष 2026 की वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियां प्रभावित हो गई हैं। इसका असर प्रदेश के हजारों कर्मचारी और अधिकारियों पर पड़ रहा है। इस वर्ष जारी किए जा रहे पदोन्नति आदेश वर्ष 2025 की वरिष्ठता तथा रिक्त पदों के आधार पर दिए जा रहे हैं। ऐसे में जिन कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2026 की वरिष्ठता सूची के अनुसार होनी थी, वे फिलहाल इससे वंचित रह गए हैं। अब सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें वर्ष 2027 की रिक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जून 2025 में लागू किए गए थे। नियमों के अनुसार वर्ष 2025 में पहली बार विशेष विभागीय पदोन्नति समिति का गठन कर पूर्व से लंबित तथा 31 दिसंबर 2025 तक की संभावित रिक्तियों पर पदोन्नति की जानी थी। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2025 में वर्ष 2026 की रिक्तियों के लिए नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें प्रस्तावित थीं। हालांकि नियमों को न्यायालय में चुनौती मिलने के कारण वर्ष 2025 में विशेष विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं हो सकी। अब वर्ष 2026 में विशेष विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें केवल 31 दिसंबर 2025 तक की रिक्तियों को शामिल किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून को पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश तो जारी किए, लेकिन नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं किया। वर्तमान स्थिति में कई विभागों को अलग-अलग वर्षों के लिए एक से अधिक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें करनी पड़ सकती हैं। इससे वरिष्ठता संबंधी विवाद की आशंका भी जताई जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग सहित कई विभागों में जुलाई 2026 में जारी पदोन्नति आदेश वर्ष 2025 की वरिष्ठता के आधार पर दिए जा रहे हैं। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग अब तक नए शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति आदेश जारी नहीं कर सका है। शासकीय शिक्षक संगठन ने देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग की है।

सड़क हादसे नियति नहीं, लापरवाही का नतीजाः जस्टिस अभय सप्रे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सागर कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की। बैठक में जस्टिस सप्रे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं किसी नियति या ईश्वर की इच्छा का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि अधिकांश मामलों में मानवीय भूल, तकनीकी खामियों और प्रबंधन संबंधी कमियों के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि यदि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए और सड़क अवसंरचना में समय रहते आवश्यक सुधार किए जाएं तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उनका लक्ष्य सड़क हादसों में मृत्यु के आंकड़े को शून्य के करीब लाना बताया गया। उन्होंने जिले में दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) पर किए गए सुधार कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आई है। साथ ही शेष चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर भी शीघ्र सुधार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सागर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश और देश के लिए एक आदर्श जिला बन सके। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक धीरज खंडेलवाल ने 21 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें गौरव अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नई कार्यकारिणी में प्रदेश सह संयोजक के रूप में विनोद गर्ग, राकेश जोशी, मंजेश जैन, गेलेंद्र राठौर, लालचंद लालवानी, श्रेयांश वैद्य, रवि केसरी, पदम खेमका, हीरालाल पाटीदार, सुनील कटारिया, संजय परवाल, अलिन्द्र त्रिपाठी तथा निर्मल अग्रवाल को दायित्व सौंपा गया है।

प्रवीण नीखरा को प्रदेश कार्यालय प्रभारी तथा आयुष खंडेलवाल को प्रदेश कार्यालय सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भगवानदास भट्टर को प्रदेश मीडिया सह प्रभारी बनाया गया है। राहुल मित्तल को प्रदेश सामाजिक माध्यम प्रभारी तथा प्रमोद मांडलिया को प्रदेश सामाजिक माध्यम सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार का प्रभारी सचिन गुप्ता (द्रोड़मार) तथा सह प्रभारी मुकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।

पहलः नीट-जेईई की निःशुल्क कोचिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के मैहर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी स्कूल स्तर पर ही कराई जाएगी। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी की पहल पर कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट और जेईई की निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषय के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं से ही व्यवस्थित मार्गदर्शन दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों का एक विशेष समूह तैयार किया जाएगा, जो नियमित अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को नीट और जेईई परीक्षा के अनुरूप तैयार करेगा।

इस कार्यक्रम में इंदौर की कोचिंग संस्था एलन का तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहयोग लिया जाएगा। संस्था जिले के 94 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यही शिक्षक मैहर जिले के विभिन्न शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 2,996 विद्यार्थियों को अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे।

विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पाठ्य सामग्री और टेक्स्ट बुक्स भी जिले के सभी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। उनका लक्ष्य है कि मैहर जिले के अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटी और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिले का नाम रोशन करें।

परमार ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों और मांगों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

परमार ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव मंत्री के समक्ष रखे, जिन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

समीक्षा *प्रत्येक निर्माण कार्य प्रदेश के विकास और जनकल्याण का माध्यम*

गुणवत्ता और समयबद्धता से पूरे हों सेतु निर्माण कार्य : राकेश सिंह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि विभाग का प्रत्येक निर्माण कार्य केवल सड़क, पुल या फ्लायओवर का निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास और जनकल्याण का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी सेतु निर्माण परियोजनाएं गुणवत्ता, समयबद्धता और पूर्ण जवाबदेही के साथ पूरी की जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वल्लभ भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने 30 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन फ्लायओवर, रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) और पुल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग, प्रभावी फील्ड निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने और तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राकेश सिंह ने कहा कि विभाग और निर्माण एजेंसियां प्रदेश के विकास की साझेदार हैं। उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि विलंबित परियोजनाओं में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आधुनिक तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी कार्यप्रणाली को अपनाने पर भी जोर दिया।

बैठक में 48 निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई, जिनमें पांच फ्लायओवर, 33 रेल ओवर ब्रिज और 10 पुल शामिल हैं। परियोजनावार प्रगति, तकनीकी चुनौतियों और विभिन्न विभागों के समन्वय की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विलंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com